Research Paper

E-ISSN NO : 2455-295X | IMPACT FACTOR VALUE : 5.983
VOLUME : 11 | ISSUE : 1 | SPECIAL ISSUE JANUARY-2025

ऋण माफी का कृषि साख और बैंकों की गैर निष्पादित संपत्ति पर प्रभाव

ओम प्रकाश शोधार्थी (अर्थषास्त्र), महाराजा गंगा सिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर.

ABSTRACT:

यह शोध-पत्र **फसली ऋण माफी योजनाओं** के प्रभाव और निहीतार्थ की जांच करता है। समय समय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें फसली ऋण माफी योजनाओं को लागु करती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 2008 में किसानों का राष्ट्रीय बैंकों का फसली. ऋण माफ किया गया। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा **"राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018"** केवल सहकारी बैंक के लघु व सीमांत किसानों का 50000/- तक का अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया जबकि **"राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2019"** के अन्तर्गत सहकारी बैंक के लघु, सीमान्त व अन्य किसानों का 150000/- तक का मध्यकालीन फसली ऋण माफ किया गया। 2018 के आसपास के चुनावी वर्षों में कई राज्यों द्वारा किसानों का ऋण माफ किया गया है। आंकडें बताते हैं कि ऋण माफी के वर्षों से पूर्व राजस्थान में कृषि साख के दिये गये लक्ष्य के विपरीत लक्ष्य प्राप्ति का स्तर कम हो रहा है जबकि 2018 के बाद लक्ष्य प्राप्ति का स्तर लगातार बढा है अर्थात किसानों द्वारा अधिक ऋण लिया गया है। दुसरी और बैंकों की कुल गैर निष्पादित संपति में लगातार गिरावट हुई है जो 2024 में 2.8 प्रतिषत हो गया है, जबकि कृषि क्षेत्र की गैर निष्पादित संपति में अभी भी उच्च स्तर बना हुआ है जो 2024 में 6.2 प्रतिशत है जो बैंकों के कुल एनपीए प्रतिशत से बहुत अधिक है क्योंकि ऋण माफी योजनाओं की उम्मीद में अधिकतर किसानों द्वारा ऋण नहीं चुकाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र की गैर निष्पादित संपति में यह हल्की गिरावट ऋण माफी योजनाओं व बैंकों द्वारा ऋणों के राइट ऑफ करने के कारण है।

KEYWORDS:

लघु व सीमान्त कृषक, फसली ऋण, राइट ऑफ।

प्रस्तावना:-

भारत में कृषि सुधार व नवप्रवर्तन हेतु समय समय पर अनेक उपाय किये जाते रहे हैं जिनमें किसानों को साहुकारों के चुंगल से निकालने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना प्रमुख है। भारतीय कृषि पूर्णतः मानसुन पर निर्भर होने के कारण किसानों को विपरित परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। कृषि की बढती लागत और फसलों के खराबे से किसानों की दषा बिगडती जा रही है ऐसी विपरित परिस्थितियों के कारण सरकारों ने समय समय पर किसानों को राहत देने के लिए फसली ऋण माफी योजना को लाया गया हैं। इसी प्रकार की एक बड़ी ऋण राहत योजना 2008 में केन्द्र सरकार द्वारा एक घोषणा करते हुए लाई गई जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से देश में लगभग 71600 करोड़ रू. का ऋण माफ किया गया। वर्तमान में किसानों को रिझाने के लिए चुनावों से पहले सभी पार्टीयों द्वारा ऋण माफी की घोषणाएं की जा रही है। राजस्थान में भी तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा **"राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018"** के माध्यम से सहकारी बैंक के लघु व सीमांत किसानों का 50000/- तक का अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया जबकि **"राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2019"** के अन्तर्गत सहकारी बैंक व प्राथमिक भूमि विकास बैंक के लघु, सीमान्त व अन्य किसानों का 150000/- तक का मध्यकालीन फसली ऋण माफ किया गया। जिसमें राजकोष पर कुल 18000 करोड़ का बोझ पड़ा। इस प्रकार की ऋण माफी से किसानों की ऋण लेने की प्रवृति बढती है व ऋण चुकाने की प्रवृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिस कारण बैंकों की गैर निष्पादित संपति भी बढती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर ऋण माफी योजनाओं को ना दोहराने का सुझाव दिया है इसलिए सरकारों द्वारा किसानों की ऋण माफी योजनाओं की एवज में नई नई तकनीक अपनाने हेतु किसानों को सहायकी दी जानी चाहिए ताकि किसान नई तकनीक अपनाकर अपनी आय को बढा सकें क्योंकि किसानों के लिए ऋण माफी योजनाऐं कोई स्थायी समाधान नहीं हैं।

ऋण माफी क्या है ?

किसानों द्वारा फसली ऋण या उपकरण खरीदने हेतु अपनी कृषि भूमि को रहन रखकर लिया गया ऋण जब चुकाने में असमर्थ हो तो सरकार ऋणों को अपने ऊपर ले लेती है और बैंकों को चुका देती है। कभी कभी बैंकों द्वारा किसानों को एकमुष्त ऋण चुकाने की शर्त पर ऋण में छुट दी जाती है। व कभी कभी बैंकों द्वारा ऋण ना आने की संभावना को देखते हुए ऋण को लेखा में से हटा दिया जाता है जिसे बैंक की भाषा में राइट ऑफ कहते हैं।

साहित्य की समीक्षा:-

1. डॉ. आर सी माथुर (2017), कृषि ऋण में सहकारी बैंक की भूमिकाः राजस्थान राज्य का एक अध्ययन में बताया कि सहकारी बैंक कृषि ऋण एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सहकारी बैंक किसानों को शुन्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करा रहे हैं जिस कारण किसान इस सेवा से बहुत संतुष्ट हैं।

2. जेएसएस कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स एण्ड सांईस ने अपने लेख कृषि ऋण माफी - अच्छा या बुरा मे निष्कर्ष में बताया कि किसानों ऋण माफी किसानों के लिए सकारात्मक परिणाम के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी दर्शाती है सरकारों को कृषि आय से ध्यान हटाकर किसानों की आय पर केन्द्रीत करना होगा अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में तथा उसके आसपास रोजगार के अवसरों का विस्तार करके किसानों की आय को बढाना होगा। इसलिए किसानों को ऋण माफी योजनाओं की बजाय, बहु विशेषताओं वाली आय सृजन योजना किसानों के संकट को कम करने में मदद कर सकती है।

3. तनिका चक्रवर्ती और आरती गुप्ता ने अपने लेख ऋण माफी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में बताया कि ऋण माफी उम्मीद में परिवारों द्वारा ऋण का अनुत्पादक व्यय किया जाता है और ऋण माफी की घोषणा के बाद युपी के सभी जिलों में ऋण चुकौती दरों में भारी गिरावट आई है

4. सिंह, विवेक राजबहादुर, (2016), "वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों का अध्ययन और भारत में इसकी वसूली" में बताया कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बढ़ाने की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। एनपीए की वृद्धि का बैंकों की लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, गैर निष्पादित परिसंपतियां भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रमुख चिंताओं में से एक है। बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए एनपीए को कम करना आवष्यक है।

5. मौर्य, सुरेश कुमार, एवं विश्वकर्मा नेहा, (2021) "भारत में कृषि साख और ऋणग्रस्तता की स्थितिः एक अध्ययन" ने निष्कर्ष निकाला कि भारत में सीमान्त भूमि आकार समूहों के लिए ज्यादातर, कृषि उद्देश्यों के लघु और मध्यम अवधि चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। भूमि का आकार बढने पर कुल कृषि परिवारों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत बढ़ता है। जोत का प्रतिशत पंजाब, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिसा और राजस्थान में ऋणी कृषक परिवारों के प्रतिशत से कम है।

6. डी 'सूजा, रेनिटा,(2020), "कृषि ऋण तक पहुंच में सुधारः नए दृष्टिकोण" में बताया कि देश के कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में वित्तीय समावेशन है।

वर्षों से भारत ने अपने किसानों के लिए वित्तीय समावेशन में अंतर कम करने के लिए विभिन्न उपायों का प्रयास किया है। फिर भी लक्ष्य देश से दुर है। उन्होनें बताया कि वित्तीय क्षेत्र को किसानों की वर्तमान वित्तीय वास्तविकताओं को समझने की जरूरत है और वित्तीय क्षेत्र को उच्च जोखिम, निम्न- गुणवत्ता वाली साख परिसंपत्तियों के बजाय एक अप्रयुक्त ऋण बाजार के रूप में माना जाना चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य:-

1. राजस्थान में फसली ऋण माफी का किसानों की साख पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. ऋण माफी का बैकों की गैर निष्पादित संपति पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. ऋण माफी के लाभ-हानियों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि:-

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से की गई फसली ऋण माफी 2018 व 2019 का किसानों की साख पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है व ऋण माफी योजनाओं का बैंकों की गैर निष्पादित संपति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन करने के लिए द्वितीयक आंकडों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में 2015 से 2024 तक की अवधि के आंकडें शामिल किए गए हैं। प्रस्तुत आंकडें नाबार्ड द्वारा जारी राजस्थान के संदर्भ में स्टेट फोक्स रिपोर्ट वर्ष 2015से 2024, भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टस वर्ष 201समाचार पत्र, वेबसाइट व पूर्व में किए गए शोध व भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा व राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा से लिए गए हैं।

आंकडों द्वारा प्रस्तुतीकरण:-

सारणी: राजस्थान में कृषि साख की प्रवृति

सत्र	लक्ष्य			उपलब्धि			प्रतिशत
	फसली ऋण	सावधि ऋण	कुल कृषि ऋण	फसली ऋण	सावधि ऋण	कुल कृषि ऋण	
2015-16	60813	19682	80495	56864	10347	67211	83
2016-17	70866	31132	101998	57317	12122	69439	68
2017-18	75594	32289	107883	61606	11181	72787	67.46
2018-19	80532	32929	113461	60146	16044	76190	67.15
2019-20	75041	25355	100396	63853	16028	79881	79.57
2020-21	85022	24426	109448	70428	20826	91254	83.38
2021-22	94321	27221	121542	87052	24652	111704	91.9
2022-23	101867	29427	131341	100045	37222	137267	104.51

स्रोत:- नाबार्ड द्वारा जारी राजस्थान स्टेट फोक्स पेपर 2015-16 से 2022-23 तक।

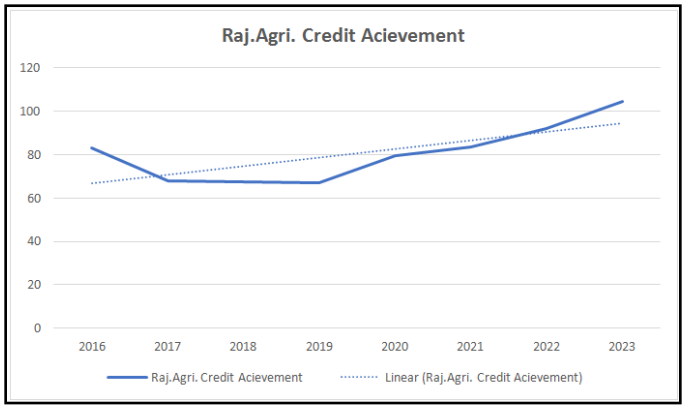

नाबार्ड द्वारा जारी राजस्थान में कृषि ऋण के आंकडों को देखने पर ज्ञात होता है कि 2018-19 तक कृषि ऋण का जो लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जा रहा था उसकी उपलब्धि प्रतिषत घट रही है जबकि 2018-19 जो कि राजस्थान में ऋण माफी का वर्ष था से कृषि ऋण का लक्ष्य उपलब्धि में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋण माफी के बाद राजस्थान में कृषि साख में वृद्धि के साथ साथ किसानों ने कृषि ऋण अधिक लिया है जो वर्ष 2022-23 में दिए गए लक्ष्य से अधिक आंवटित किया गया है।

भारत में बैंकों के कुल गैर निष्पादित संपति का कृषि क्षेत्र के गैर निष्पादित संपति से तुलनात्मक अध्ययन:-

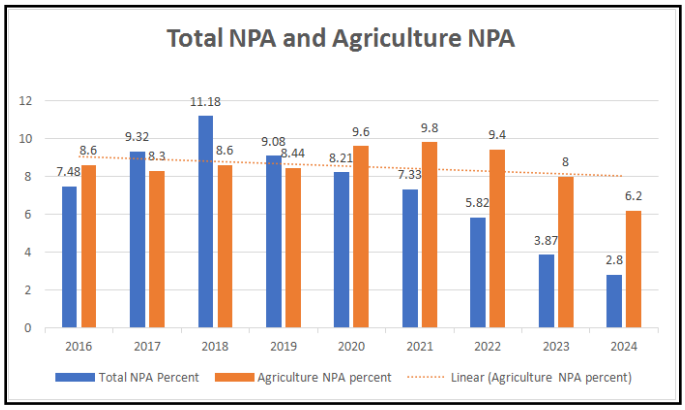

स्रोत:- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वर्ष 2016 से 2024 व नाबार्ड द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 से 2022-23 तक।

आंकडों से ज्ञात होता है कि भारत में बैंकों की कुल गैर निष्पादित संपति में 2018 के बाद तेज गति से गिरावट देखने को मिल रही है व कृषि क्षेत्र में भी गिरावट देखने को मिल रही है परन्तु यह गिरावट बहुत धीमी गति से हो रही है। बैंकों की कुल गैर निष्पादित संपति 2018 में 11.18 प्रतिशत के अधिकतम स्तर से गिरकर 2024 में 2.8 प्रतिशत तक तेज गिरावट हुई है जबकि कृषि क्षेत्र में गैर निष्पादित संपति 2024 में भी 6.2 प्रतिषत बनी हुई है। कृषि क्षेत्र के एनपीए में यह धीमी गिरावट ऋण माफी योजनाओं की उम्मीद के कारण है क्योंकि ऋण माफी योजनाओं की उम्मीद के कारण किसानों द्वारा ऋण नहीं चुकाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में गैर निष्पादित संपति में यह कमी बैंकों द्वारा ऋण माफी योजनाओं व ऋणों के राइट ऑफ के कारण है।

कृषि ऋण माफी- अच्छा या बुरा

वर्तमान में प्रत्येक चुनाव में कृषि ऋण माफी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है प्रत्येक राजनीतिक दल किसानों को रिझाने के लिए बिना सोचे-समझे कृषि ऋण माफी की घोषणाएं किए जा रहे है। कुछ विद्वान कृषि ऋण के पक्ष में है जबकि कुछ विद्वान इसकी आलोचना भी करते है।

ऋण माफी के पक्ष में तर्क:-

- **किसानों को राहत-** विपरीत परिस्थितियों में जब किसान अपना ऋण चुकाने पाने में असमर्थ प्रतीत होते है ऐसे समय में किसानों को दी गई छोटी राहत भी उनके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।
- **किसान के सामथ्र्य में वृद्धि-** ज्यादातर छोटे कर्जदार किसान अपनी उत्पादकता बढाने के लिए और अधिक निवेश करनें में समर्थ नहीं होते इसलिए कृषि ऋण माफी योजनाऐं किसानों को उत्पादकता बढ़ानें के लिए निवेष करने हेतु प्रेरित करती है।
- **किसानों का उत्थान-** भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निदेशक तत्वों के अनुसार भी लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का निर्देश दिया गया है। कृषि ऋण माफी का बढ़ता कदम भी किसानों के कल्याणकारी और उनकी सामाजिक असमानताओं को कुछ कम करनें में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- **किसानों की आत्महत्या को कम करनें में सहायक-** किसान अपनी जमीन बिकनें के श्य से या सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पंहुचे के भय से आत्महत्या कर रहे है। विभिन्न शोधों से निष्कर्ष निकाला गया है कि कृषि ऋण माफी से किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा कम हुआ है।
- **नए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा-** जोखिम के भय से ज्यादातर किसान नई

तकनीक अपनाने में हिचकिचाहट महसूस करते है यदि उनके कृषि ऋण माफी किया जाए तो वह नई प्रौद्योगिकी अपना सकेंगे जिससे दूसरे किसान भी इनसे प्रेरित होंगे।

ऋण माफी के विपक्ष में तर्कः-

- **ऋण ना चुकाने की नकारात्मक प्रवृतिः-** ऋण माफी योजनाओं के कारण किसानों में ऋण ना चुकाने की नकारात्मक प्रवृति बढ रही है क्योंकि ऋण माफी योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो ऋण समय पर नहीं चुकाते हैं।
- **बैंकों के एनपीए में वृद्धिः-** ऋण ना चुकाने के कारण बैंकों का एनपीए बढता है जिस कारण बैंकों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक पड़ता है।
- **गैर उत्पादक व्यय में वृद्धिः-** ऋण माफी योजनाओं के कारण किसान ऋणों को उत्पादक व्यय के बजाय गैर उत्पादक व्यय कर रहे हैं जिस कारण किसान समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ साबित होते हैं।
- **राजकोष पर अतिरिक्त बोझः-** ऋण माफी योजनाओं के कारण राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है अन्यथा यह राशि राज्य की विकासात्मक कार्यों पर खर्च कर विकास की गति तीव्र की जा सकती है।
- **जरूरतमंद किसानों को समय पर सहायता नहीं:-** कुछ किसानों द्वारा समय पर ऋण ना चुकाने के कारण बैंक जरूरतमंद किसानों को समय पर व आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं करवाते हैं।

REFERENCES

1. Maurya, Suresh kumar and Vishvakarma, Neha (2021), Þ Study of Agriculture credit and Indebtedness in india: An Analysisß May 19, 2021, 69(1),24-31

2. Rbi, ßReport of the Internal Working Group to Review Agricultural CreditÞ 6, September 2019

3. Singh, Vivek Rajbahadur(2016) A Study of Non-Performing Assets of Commercial Banks and it's recovery in India, Annual Research Journal of Symbiosis Centre for Management Studies, Pune Vol. 4, March 2016

4. Tanika Chakravarti and arti gupta,IIT Kanpur Efficancy of loan Waiver programs. JEL 017

5. Renita d'Souza, 'Improving Access to Agriculture credit New perspectives' ORF occasional pepar No. 230, January 2020, Observer Research Foundation.

6. Dr. R.C. Mathur, Role of Cooperative Bank in Agriculture Credit:A Study of Rajasthan State

7. State focus Report, Rajasthan Releases By NABARD 2015 to 2024

8. NABARD Annual Report 2018-19 to 2022-23

9. Financial Stability Report Releases By Reserve Bank Of India June 2016 to June 2024

10. Vijayalakshmi R (2014), A Study on evolution of Agriculture debt waiver and debt relief scheme 2008"